

Investment to be done for basic infrastructure

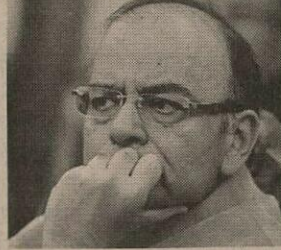
'बुनियादी ढांचे पर होगा निवेश'

भाषा

नई दिल्ली, 25 मार्च

विनिर्माण क्षेत्र की निम्न वृद्धि से चिंतित वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च बढ़ाने, विदेशी निवेशकों के लिए प्रवेश आसान बनाने तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने पर बल देने का वादा किया, ताकि आर्थिक वृद्धि को गति मिल सके।

उन्होंने निम्न ब्याज दर व्यवस्था की वकालत की और भूमि अधिग्रहण विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इससे गैर-शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा। 'ग्रोथ नेट' सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा, "हमारे पास ऐतिहासिक मौका फिर से आ गया है और हमें इसका



अरुण जेटली, वित्त मंत्री

अधिकतम उपयोग करना है।' मंत्री ने उम्मीद जताई कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 20 अप्रैल से शुरू बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमारा विनिर्माण क्षेत्र एक चुनौती है और यही वह क्षेत्र है जहां हमें वास्तव में वृद्धि का प्रमुख क्षेत्र बनाना है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां देशा हमसे आगे निकल गए। चीन इसका स्पष्ट उदाहरण है।'

जेटली ने कहा, 'हमारा ध्यान 'मेक इन इंडिया' पर है, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए विभिन्न तरीके तलाशने पर है। यह एक क्षेत्र है जहां हमें गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।' वित्त मंत्री ने कहा कि आज सुबह राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, 'ये मुद्दे हमें विरासत में मिले हैं। अकेले राजमार्ग क्षेत्र में एक या अन्य चीजों को लेकर 77 परियोजनाएं अटकी हुई हैं।' उन्होंने कहा, 'कुछ मुद्दों को सुलझाने से इनमें से 24 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।' रक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि वह इस मामले में थोड़ा आशावादी हो रहे हैं क्योंकि क्षेत्र में कुछ गतिविधियां हो रही हैं। जेटली ने कहा, 'विदेशी निवेशक घरेलू विनिर्माताओं के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, बड़े समूह इस विशेष क्षेत्र में प्रवेश को लेकर रुचि दिखा रहे हैं।'